संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 24 नवंबर, 2017 : मार्गशीर्ष शुक्ल 6 वि. 2074

जो कुछ नहीं करता केवल वही गलतियां नहीं करता

ईवीएम पर फिर निशाना

अब यह और स्पष्ट है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधने को अपने शौक के साथ अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। इस क्षुद्र राजनीति का अहम हिस्सा है अर्ध सत्य को सत्य के तौर पर पेश करना। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान मेरठ में एक ईवीएम में गड़बड़ी के बाद एक बार फिर यह शोर मचाए जाने पर हैरानी नहीं कि ऐसी ईवीएम अमल में लाई जा रही हैं जिनमें बटन कोई भी दबाएं, वोट कथित तौर पर भाजपा के खाते में ही जाता है। इस शोर के समर्थन में एक वीडियो का भी हवाला दिया गया। हालांकि यह वीडियो यही दर्शाता है कि ईवीएम का बटन दबाने पर भाजपा के चुनाव निशान के साथ नोटा निशान के समक्ष भी लाइट जलती है, लेकिन अपनी राजनीतिक सुविधा और सनसनी के लिए इसे इसी रूप में प्रचारित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत शुरू कर दी गई कि कोई भी बटन दबाओ, वोट तो भाजपा के नाम ही जा रहा है। यह मेहनत शरारती तत्वों और छुटभैये नेताओं के साथ कई राजनीतिक दलों की ओर से भी की गई। इनमें वे भी शामिल हैं जो ईवीएम के जरिये ही चुनावी जीत हासिल कर चुके हैं। ध्यान रहे कि चंद माह पहले मध्यप्रदेश में भिंड में एक ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर भी शरारत भरा दुष्प्रचार किया गया था। इस शरारत में मीडिया का भी एक हिस्सा शामिल था। उसकी ओर से यह झूठ फैलाया गया कि गड़बड़ी सामने आने पर अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को धमकाया। इसके बाद दिल्ली विधानसभा में एक नकली ईवीएम में सेंध लगाने का स्वांग किया गया। जब सुनियोजित और प्रायोजित झूठ से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम में छेड़छाड़ करने की चुनौती पेश की तो सबने अपने कदम पीछे खींच लिए।

मेरठ में ईवीएम की गड़बड़ी का मसला सामने आते ही दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने तो ईवीएम पर संदेह जताया ही, शिवसेना और कांग्रेस ने भी रोना-पीटना शुरु कर दिया। ये राजनीतिक दल यही काम पहले भी कर चुके हैं। क्या यह वही शिवसेना नहीं जो मुंबई के निकाय चुनाव में सबसे आगे रही थी? यह भी किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस ने पंजाब में ईवीएम के जरिये ही उल्लेखनीय चुनावी सफलता अर्जित की थी और अभी हाल में चित्रकूट विधानसभा के उपचुनाव में भी उसे ही जीत मिली है। कांग्रेस ने मेरठ का मामला सामने आते ही जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से जांच की मांग की उससे यही पता चलता है कि उसका इरादा ईवीएम को जानबूझकर संदेह के कठघरे में खड़ा करना है। कांग्रेस ने नया तर्क यह खोजा है कि ईवीएम की पारदर्शिता के लिए केवल वीवीपीएटी यानी मतदान बाद निकलने वाली पर्ची ही काफी नहीं है। निःसंदेह निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हर तरह के संदेह का निवारण करे, लेकिन जब कुछ राजनीतिक दलों ने यह ठान लिया हो कि वे हर हाल में संदेह करते ही रहेंगे तो फिर उसका इलाज किसी के पास नहीं हो सकता।

हेलमेट के लिए सख्ती

सड़क हादसों की संख्या में दिनोंदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देखा गया है कि दुर्घटना होने पर हेलमेट लगाए बाइक सवार की जान तो बच जाती है पर पीछे बैठने वाली सवारी को गंभीर चोट आती है। कई बार इसी कारण अनहोनी तक हो जाती है। ऐसी घटनाएं कम हों, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, यह बात सभी जानते हैं पर इस नियम का पालन करने में कोताही बरतते हैं। उनके साथ-साथ पुलिस और प्रशासन भी लापरवाह है। आम जनता यातायात के नियमों का पालन करे, यह सुनिश्चित कराना पुलिस और प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। अक्सर बड़ी वारदात हो जाने के बाद ही चौराहों पर पुलिसकर्मी वाहन चालकों को रोककर उनसे जरूरी कागजात और हेलमेट के बारे में पूछताछ करती है। सामान्य दिनों में लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं और पुलिस भी ध्यान नहीं देती।

अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर उनसे पूछताछ करते तो हैं पर उन पर कार्रवाई करने से बचते हैं

दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले कई सालों से अनिवार्य है और वहां की जनता इस नियम का पालन भी करती है। कारण है दिल्ली पुलिस की सख्ती। लोग जानते हैं कि चौराहे पर बिना हेलमेट देखे जाने पर तत्काल चालान होगा। जब तक ऐसी सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं होती, तब तक सड़क हादसों में कमी लाना आसान नहीं होगा। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर उनसे पूछताछ तो करते हैं पर कार्रवाई करने से बचते हैं। आम लोगों को भी समझना चाहिए कि हेलमेट उनकी रक्षा के लिए है। लिहाजा एक तो उन्हें यह पहनना चाहिए और दूसरे, सस्ते हेलमेट से बचना चाहिए क्योंकि मौके पर वे खुद खील-खील हो जाते हैं और सिर नहीं बचा पाते।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कानून बनाने से देश में तीन तलाक की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी?

आज का सवाल

क्या भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के लिए यो-यो फिटनेस टेस्ट को कसौटी बनाया जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अंदेशे के भय से उपजा असंतोष

ए. सूर्यप्रकाश

राजपूत संगठनों की अतिरंजित व्यग्रता उनके इस डर में देखी जा सकती है कि बॉलीवुड रानी पद्मावती की साहसिक-सुंदर छवि विकृत करने पर आमादा दिखता है

पहली नजर में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' के सामूहिक विरोध के पीछे कोई तर्क नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्वयं कबूला है कि उन्होंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में खासकर राजपूत समुदाय और अन्य हिंदू जातियों के लोग सड़कों पर आकर फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि भंसाली ने संभवतः अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी उर्फ पद्मावती के बीच कुछ ऐसे रोमांटिक दृश्य फिल्माए हैं जो हिंदू समुदाय में निंदनीय माने जाते हैं। हालांकि कुछ मीडिया पेशेवरों, जिनके लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी, ने इन अफवाहों को आधारहीन बताकर विरोध की आग को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि फिल्म में दोनों पात्र-पद्मावती और खिलजी कहीं भी एक साथ नहीं आए हैं। बावजूद इसके विरोध जारी है। इससे प्रतीत हो रहा है कि उनका भय कितना बढ़ गया है। राजपूत समुदाय के प्रतिनिधियों की उग्र और तर्कहीन प्रतिक्रियाओं को छद्म सेक्युलर और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखे भारतीय इतिहास खासकर मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रति हिंदू समुदाय के अविश्वास के रूप में भी देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने ढेरों तथ्यहीन कहानियां गढ़ रखी हैं। उन्होंने औरंगजेब पर सेक्युलर होने का ठप्पा लगा रखा है, लेकिन लंबे समय से इसे कोई चुनौती देने वाला नहीं है, जबकि लोग जानते हैं कि वह एक ऐसा निरंकुश शासक था जिसने मंदिरों को न सिर्फ लूटा, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता की सारी हदें लांघी। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक इस सच्चाई को स्वीकारने में इन बुद्धिजीवियों ने बौद्धिक बेईमानी का परिचय दिया, जबकि देश की मौखिक ऐतिहासिक परंपरा के जरिये वे इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ थे।

चूंकि 2014 तक नई दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर नेहरूवादी और वामपंथी विचारकों की पकड़ थी, लिहाजा साहित्य और सिनेमा में उनका प्रभाव बढ़ता गया। इससे कला जगत के लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि वे अपनी कला के जरिये हिंदुओं को नीचा दिखाने को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताने लगे, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है। इसके दो कारण हैं। पहला, लोगों ने झूठ पर सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि कला के आधुनिक रूप सिनेमा ने उसे काफी विस्तार दिया है। दूसरा, शिक्षा जगत में मौजूद वामपंथी विचारकों की कुटिल चालों के बावजूद देश में कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जिन्होंने उनकी मिथ्या बातों से पर्दा उठाने का भरसक प्रयास किया है और इतिहास को सच के करीब लाए हैं। आरसी मजूमदार से लेकर प्रो. केएस लाल, डॉ. एसपी गुप्ता, प्रो. मक्खन लाल और प्रो. बीबी लाल ऐसे ही कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने उनके प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को चुनौती दी है। यह भूल सुधार अभी शुरुआती दौर में है। पद्मावती फिल्म को लेकर अतिरंजित भय इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

अवधेश राजपूत

अब अलाउद्दीन खिलजी पर वापस लौटते हैं। कहा जाता है कि वह आठ जनवरी, 1303 को दिल्ली से चितौड़ के लिए रवाना हुआ। एक थ्योरी, जो कि ज्यादा प्रभावी है, कहती है कि वह अनेक राज्यों को जीतना चाहता था और विश्व विजेता बनना चाहता था। दूसरी थ्योरी कहती है कि वह रानी पद्मावती पर मोहित था और उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। यहां तक कि इसके लिए उसने ढेरों कुचक्र रचे और खूनी लड़ाइयां भी लड़ीं। वह लंबे समय तक चितौड़गढ़ के किले को घेरे रहा। राजपूत इतिहास और संस्कृति को लिपिबद्ध करने वाले इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार खिलजी ने बेरच और गंभीरी नदियों के बीच डेरा डाल दिया था। उसकी घेरेबंदी के चलते राजा रतन सिंह ने हार मान लेने का फैसला किया, लेकिन उनके लोगों ने कुछ और समय तक लड़ने का निर्णय किया। 'युद्ध उपरांत किले पर जब खिलजी का कब्जा हुआ तब एक दिन में ही 30 हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया।' इसी के साथ पद्मावती और उनकी सहेलियों ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया अर्थात जौहर कर लिया। दशरथ शर्मा पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि 'पद्मावती को जीवित हासिल करने के लिए हरसंभव कुचक्र रचने के बावजूद अलाउद्दीन के हाथ दो मुट्ठी राख के अलावा कुछ नहीं आया।' कई इतिहासकारों ने जायसी की कविता के आधार पर ही अपनी बातें आगे बढ़ाई हैं। शर्मा कहते हैं कि राजस्थान की शायद ही किसी अन्य नायिका ने पद्मिनी से ज्यादा कवियों और लेखकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हो। उनकी रचनाओं में उनके विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सभी के केंद्र में यही है कि 'बहादुर, सुंदर और अदम्य पद्मिनी एक लंपट और क्रूर शासक को चकमा देने में सफल रहीं और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा की खातिर अपने आप को आग के हवाले कर दिया।' रानी पद्मावती के बारे में लोकजन में प्रचलित कथा का सार भी यही है। दशकों से पद्मावती की यह कहानी भारतीयों के दिलो-दिमाग में बैठी हुई है। यह शैक्षणिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जौहर करने के पद्मावती के निर्णय को राजपूत और अन्य हिंदू जातियां सर्वोच्च वीरता के रूप में देखती हैं। इससे लोगों के मन में पद्मावती का दर्जा एक देवी के रूप में है। राजपूत संगठनों की अतिरंजित व्यग्रता उनके इस डर में देखी जा सकती है कि बॉलीवुड रानी पद्मावती की साहसिक और सुंदर छवि को विकृत करने पर आमादा दिखता है। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि पद्मावती का वजूद था। वह काल्पनिक चरित्र नहीं हैं। उन्होंने उन मूल्यों की रक्षा की जो एक भारतीय नारी को प्रिय हैं। हालांकि इस उग्र विवाद के दौरान ही देश के कुछ जाने-माने वामपंथी बुद्धिजीवी न सिर्फ इन मान्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पद्मावती को काल्पनिक चरित्र बताकर उनकी भावनाओं से भी खेलने का काम कर रहे हैं।

बॉलीवुड को ऐसे दुःसाहसी बुद्धिजीवियों से बचना चाहिए जो खुलेआम हिंदू मान्यताओं और मतों को चुनौती देते हैं। एक बार समस्या की जड़ पकड़ में आ जाने पर भंसाली की टीम के लिए इसका निराकरण करना आसान हो जाना चाहिए। हालांकि यदि पद्मावती की छवि से फिल्म में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है तो संजय लीला भंसाली ने इस विवाद को आरंभ में ही ठंडा करने का प्रयास क्यों नहीं किया? जाहिर है बॉलीवुड जब बुराई और संकट के स्रोतों की पहचान कर लेगा, जो कि नेहरूवादी और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखित नकली इतिहास है, तब वह एक समुदाय से टकराव को टालने में भी सक्षम हो जाएगा। बहरहाल भारतीय शासन व्यवस्था का यह कर्तव्य बनता है कि वह संजय लीला भंसाली की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिल्म के कलाकारों को जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

(लेखक प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

लौटें परंपरागत खेती की ओर

राजनाथ सिंह 'सूर्य'

पुरानी भारतीय जीवनशैली ही प्राकृतिक विनाश से होने वाले भयावह माहौल से बाहर निकाल सकती है

बढ़ते प्रदूषण पर दुनिया भर में चिंता अवश्य व्यक्त की जा रही है, किंतु उसके समाधान के मूलभूत पहलू की उपेक्षा हो रही है। भौतिक सुख की बढ़ती भूख के कारण आधुनिकता और प्रगतिशीलता के नाम पर प्रकृति के शोषण पर विराम लगे बिना समाधान खोजना अंधेरे में सुई खोजने से भी कठिनाई भरा है। नित्य प्रति हम अपने आचरण से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। हरे-भरे वनों का तो अभाव हो ही रहा है, न जाने कितनी नदियां सूख गईं और जो हैं भी उनमें 20 वर्ष पूर्व के मुकाबले आधा भी जल प्रवाहित नहीं हो रहा है। दूसरी ओर धुआं उगलने वाली गाड़ियों, कृषि में काम आने वाले यांत्रिक उपकरणों, उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग की अधिकता से ऐसे पौधे और कीड़े मकोड़ों की अधिकता बढ़ रही है जो केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। जहां दुनियाभर के देश वर्ष में एक बार किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हैं वहीं धरती ही नहीं अंतरिक्ष को भी प्रदूषित करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होड़ में भी लगे रहते हैं। पिछले दिनों दिल्ली और उसके आसपास छाए प्रदूषण के चलते स्कूल बंद कर दिए गए और देश भर में बढ़ते प्रदूषण के आंकड़े पेश किए जाने लगे। इसी बीच सामने आया कि जड़ के बजाय पत्तियों को सींचने से हरियाली बनाए रखने के समान ही वर्षा जल संचयन के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए किए गए उपाय अभी तक अनुपयोगी साबित हुए हैं और फिर भी उन्हें अपनाने की अनिवार्यता की ओर बढ़ा जा रहा है।

हमारे मनीषियों ने प्रकृति संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता जैसे संस्कार दिए थे। विश्व भर में यह स्वीकार किया जा चुका है कि भारतीय जीवनशैली ही प्राकृतिक विनाश से होने वाले भयावह माहौल से बाहर निकाल सकती है, लेकिन हम भारतीय ही भौतिकता के प्रवाह में आगे निकलने की होड़ में विनाश की दिशा पकड़ चुके हैं। प्रति वर्ष करोड़ों पौधारोपण के बावजूद वृक्षों की संख्या घटती जा रही है, नदियों की सफाई, गहराई बढ़ाने की योजनाएं नाजायज तरीके से धनार्जन का माध्यम बन गई है और हम देसी-विदेशी 'विशेषज्ञों' को मोटी रकम देकर इस स्थिति से निपटने के लिए उनसे उपाय बताने की अपेक्षा दायित्व सौंपकर अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ लेते हैं। दिल्ली और आसपास प्रदूषण का कारण हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा धान की फसल का अवशेष यानी पराली जलाना बताया गया।

गन्ने की फसल कटने के बाद अधिक उपज की नीयत से उसके ठूंठ को जलाने का भी आम रिवाज है। जब भी कुछ जलेगा उससे धुआं उठेगा ही और आकाश में नमी होने, वायु प्रवाह न होने के कारण वह आसपास ही छाया रहेगा जो श्वास लेने में कठिनाई के साथ ही कई बीमारियों के आमंत्रण का निमित्त बनेगा।

अन्न हमारी आवश्यकता है। उसका उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता। साथ ही बिना पौधे के अन्न हो भी नहीं सकता। पहले ये पौधे भूसे के रूप में पशु आहार बनते थे तो कुछ अन्य को छप्पर बनाने या इसी प्रकार के अन्य घरेलू काम में उपयोग किए जाते थे। अब न तो आधुनिक घरों में उनकी जरूरत है और न यांत्रिक कृषि के कारण पशु आहार के रूप में उनकी उपयोगिता है। ऐसे में उसे जलाने के अलावा विकल्प क्या बचता है? इस समस्या की विकरालता को देखते हुए हमारे कुछ किसानों ने खेती के परंपरागत तरीकों को अपनाकर जो उदाहरण पेश किया है उसका अनुसरण संभवतः सबसे उपयुक्त समाधान होगा, क्योंकि बैलों से खेती न होने के कारण जो बछड़ों को कसाईखाना नहीं भेजना चाहते वे उसे छुट्टा छोड़ देते हैं और वे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर शहरों में सड़कों पर घूमते हुए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे सरकारी उपाय ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। यदि परंपरागत कृषि के परिणामों का सम्यक अध्ययन किया जाए तो न तो रासायनिक उर्वरक की जरूरत होगी और न उसे संरक्षित रखने के लिए रासायनिक तरल पदार्थों की। हरित क्रांति के नाम पर अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों, हानिकारक कीटनाशकों, हाइब्रिड बीजों, अधिकाधिक भूजल उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति, उत्पादन, भूजल स्तर और मानव स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती जा रही है। बढ़ती लागत, बाजार पर निर्भरता और आधुनिकता के नाम पर सरकारी कृषि नीति के कारण किसान आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। जैविक खेती जैसी वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट बायोडायनामिक इतनी जटिल है कि किसान उनके बजाय बाजार में मिलने वाले उर्वरक पर अधिक निर्भर रहता है।

क्या कोई ऐसी पद्धति है जिससे किसानों को खाद बीज के लिए बाजार पर न निर्भर रहना पड़े, उत्पादन न घटे, खेत उपजाऊ बना रहे और मनुष्य रोगग्रस्त न हो। कुछ किसानों ने प्रयोग के आधार पर जो परिणाम प्राप्त किए हैं उसके आधार पर शून्य लागत की खेती को अपनाकर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। शून्य लागत खेती को अपनाना सरल है। इसकी विधि और महत्ता बताने वाले आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में होते रहते हैं। इन आयोजनों में किसानों को प्रकृति से तालमेल, देसी गाय पालन, देसी केंचुए के महत्व, गौमूत्र आधारित खाद और छिड़काव, वनों से सूखी खाद की उपलब्धता, भूमि के शोधन और संवर्धन, सिंचाई के तरीके और बहुफसली पद्धति को अपनाने के तरीके बताए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन दिसंबर में लखनऊ में भी होने जा रहा है। शून्य खेती के पुरोधा पुणे के सुभाष पालेकर का दावा है कि एक देसी गाय के सहारे ही दस से तीस एकड़ तक खेती की जा सकती है। एक किसान विचारक ने ठीक ही कहा है कि गाय का दूध तो सह उत्पाद (बाइ प्रोडक्ट) है, क्योंकि दूध कुछ ही महीने मिलता है जबकि गोबर और मूत्र दैनिक उत्पाद हैं जिनका सम्यक उपयोग करने के बजाय हम केवल सह-उत्पाद पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिसकी मिलावट के कारण गुणवत्ता घटती जा रही है। स्वस्थ रहने के लिए जिस प्रकार योग विश्वव्यापी बना है वैसे ही खेती में आमूलचूल परिवर्तन कर न केवल स्वास्थ्यवर्धक अन्न उत्पादन करने के लिए कृत्रिम उपायों से बचा जा सकता है, बल्कि पर्यावरण को दूषित होने से भी रोका जा सकता है।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर

भौतिक विज्ञानवादी जिस शक्ति को प्रकृति मानते हैं, उसे अध्यात्मवादी ईश्वर कहते हैं। मतभेद ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के संबंध में है। ऐसे मतभेद तो प्रायः सभी समूहों में मिल जाते हैं, परंतु उन्हें अनीश्वरवादी नहीं कहा जाता। फिर भौतिक विज्ञानवादियों को नास्तिक कहना उचित न होगा। ईश्वर को हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते तो भी यह कहना अनुचित होगा कि ईश्वर नहीं है। बहुत सी वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते तो भी अनुमान के आधार पर उनका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। यह बात हम इंद्रियों की सहायता से नहीं जान सकते, आंखों से भी नहीं देख सकते तो भी अनुमान यह कहता है कि उसको बनाने वाला अवश्य रहा होगा। ईश्वर को छुआ या देखा नहीं जाता तो भी उसकी कृतियां पुकार-पुकार कर साक्ष्य दे रही हैं कि हमारा रचयिता कोई न कोई अवश्य है। अपने स्वल्प ज्ञान के द्वारा बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से हमें विश्व ब्रह्मांड का थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त होता है। समस्त सृष्टि इतनी विस्तीर्ण है कि बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं हो पाती। यह महान रचना किसी न किसी निर्माता की कृति है। बिना व्यवस्था के तो हमारे छोटे-छोटे काम भी नहीं चलते, फिर इतनी बड़ी सृष्टि का काम बिना किसी संचालन के किस प्रकार चल सकता है।

सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, इतने नियमबद्ध हैं कि कभी एक सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ता। दिन के बाद रात होने की श्रृंखला कभी टूट नहीं पाती। बचपन के बाद जवानी, फिर वृद्धावस्था आती है। उन मूल नियमों के समझने वाले तत्वज्ञानी विवेकवानों को समस्त सृष्टि में एक रंचमात्र भी अव्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती। स्पष्ट है कि इस सुव्यवस्थापूर्वक संचालित सृष्टि को चलाने वाला कोई अवश्य होना चाहिए। मोटर, जहाज या रेल को बनाने वाला और चलाने वाला कोई विवेकवान मनुष्य होता है। उसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने और चलाने वाली शक्ति भी ईश्वर है। आज विज्ञानवादियों को यह मानना पड़ रहा है कि जड़ तत्व ही सृष्टिकर्ता नहीं है वरन यह पंचभूत भी एक आद्यशक्ति की धाराएं हैं। वह आद्यशक्ति अंधी, जड़ नहीं, बल्कि विवेकवान, फलवान, व्यवस्था रखने वाली, संशोधन करने वाली और संतुलन को ठीक बनाए रखने वाली भी है।

अवधविहारी शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

गुजरात का चुनावी दंगल

गुजरात की चुनावी हवा शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय कुमार ने चुनाव पूर्व सर्वे के आधार पर गुजरात के चुनावी दंगल का जो परिदृश्य प्रस्तुत किया है, उससे फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। लगभग दो दशकों से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस का गुजरात में छटपटाना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हार्दिक पटेल जैसे नवोदित स्थानीय नेता से की गई जुगलबंदी कांग्रेस को कितना सशक्त बना पाएगी, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। बावजूद इसके अखाड़े में अपने सामने वाले खिलाड़ी को कमतर आंकना बुद्धिमानी नहीं है। इस दृष्टि से भाजपा को बेहद सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस के पास खोने को भले ही कुछ न हो, लेकिन अपनी कोशिश से वह जितना कुछ पा लेगी, वह उसके सिमटते अस्तित्व में जान फूंकने के लिए काफी होगा। दूसरी ओर भाजपा के लिए गुजरात का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस की बढ़त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर जो भी आंच आएगी, उसकी तपिश 2019 के आम चुनाव में भी महसूस की जाएगी। pandeyvp1960@gmail.com

महिलाओं का उत्थान

संविधान में पुरुष और महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। समाज में कुछ लोगों की संकीर्ण सोच महिलाओं को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेल रही है। महिलाए घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। बहुत से परिवारों में लड़कियों को डर से शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा जाता है। कम उम्र में शादी कर दी जाती है। आधुनिक समय में भी ज्यादातर माता-पिता महिला-पुरुषों के समानता के अधिकार पर संवाद नही करना चाहते। जबकि जिस भी क्षेत्र में महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया है। हमें हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबर का अवसर देना होगा। mkumar.sidhmukh@gmail.com

विश्व में भारत

अंतरराष्ट्रीय अदालत में जस्टिस दलवीर भंडारी की जीत ने साबित कर दिया है कि दुनिया में भारत का दमखम बढ़ गया है। इसके लिए कूटनीतिक कोशिश में भारत पूरी तरह सफल हो गया है। पाकिस्तान को भारत से मिली करारी चपत से पता चल गया होगा कि इस्लामिक देशों के संगठनों ने उनकी नहीं भारत की ही बात को मानकर मतदान किया है। विश्व स्तर पर अलग- अलग विचार धारा के देश होते हैं। ऐसी कठिन स्थिति में कई देशों को अपने समर्थन में लाना बड़ी चुनौती होती है। यह जीत कूटनीति कोशिशों से भारत ने जीती है।

jay.rane555@gmail.com

भारत के लिए गर्व

भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपना परचम लहरा कर इतना तो बता ही दिया कि सत्य और विश्वास का रास्ता हमेशा सफलता की तरफ ही जाता है। पाकिस्तान कभी नही चाहेगा कि भारत से कोई यहां पहुंचे और इसके लिए उसने अपने स्तर पर खूब माथापच्ची भी की, लेकिन 193 देशों में से 183 देशों के समर्थन के आगे पाक घुटने के बल आ गया, इसके साथ ही ब्रिटेन को भेजने का इसका सपना भी चकनाचूर हो गया। प्रतिद्वंद्वी ब्रिटेन भी अपनी हैसियत को समय से पहले भांप गया और चुनाव से बाहर हो गया, यह ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी हार है। क्योंकि एक अस्थायी सदस्य स्थायी सदस्य को हराकर उस सीट पर काबिज हुआ है। चुनावी लड़ाई में भारत के दलवीर भंडारी ने दूसरी बार जज बन कर अपनी दावेदारी दर्ज कर ली। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए गर्व की बात है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत?

अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और संप्रग सरकार में मंत्री रहे श्री फारूख अब्दुल्ला ने बयान देकर और बहुत जोर देकर यह कहा है कि पीओके पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा और जो हिस्सा भारत के पास है वह भारत का ही रहेगा। कितने अफसोस की बात है कि कश्मीर के सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके श्री अब्दुल्ला ऐसी भाषा बोल रहे है। यह सर्वविदित है कि कश्मीर के तत्कालीन राजा श्री हरिसिंह ने अपनी रियासत कश्मीर का विलय भारत में पूरी तरह से कर दिया था। परंतु उसी दौरान पाक ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू इस समस्या को सही ढंग से नहीं निपटा सके और उसी का नतीजा है कि कश्मीर समस्या आज भी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। सिरदर्द तो हैदराबाद भी बन जाता यदि सरदार पटेल उस समय सख्ती न दिखाते। नेहरू जी के समय से भारत तीन समस्याओं का सामना करता आ रहा है। पहली कश्मीर समस्या दूसरी पंजाब समस्या और तीसरी भाषा समस्या। ये तीनों ही आज तक सुलझ नही सकी है। अब्दुल्ला को कहना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान भारत के उस भूभाग को तुरंत खाली करे जिस पर उसने जबरन कब्जा जमा रखा है पर बोले उल्टा ही। एक बात और भारत ने कई ऐसे मौके गवाएं है जब वह पाकिस्तान से कश्मीर को खाली करवा सकता था। शिमला समझौते के समय दूसरा उस समय जब भारत की सेनायें लाहौर तक पहुंच थी। भारत चाहता तो 1971 के युद्ध के समय भी पाक से कश्मीर को खाली कराया जा सकता था पर पता नहीं क्यों श्रीमती इंदिरागांधी ने ऐसा नही किया। यदि यही हालत रही तो हम अगले और कई दशक ऐसे ही सिर्फ बयानबाजी ही करते रहें कि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है।

इन्द्र सिंह धिगान, 3 रेडियो कालोनी, किंग्जवे कैंप दिल्ली 110009

ट्वीट-ट्वीट

भाजपा और कांग्रेस दफ्तरों में एक सकारात्मक पक्ष देखने को मिल रहा है कि वहां तमाम युवा दिख रहे हैं जिससे आभास होता है कि ये किसी टेक कंपनी का कार्यालय है।

नरेंद्र नाथ मिश्रा@iamnarendranath

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्रकार को जेल भेजने का फैसला हैरान करता है। इन दिनों सभी दलों में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ी है और पत्रकार उनके आसान शिकार बन रहे हैं।

सागरिका घोष@sagarikaghose

समय आ गया है कि भारत अपनी वृद्धि दर को तेजी दे, क्योंकि मौजूदा हालात के मुताबिक चीन की बराबरी करने के लिए हमें बीस वर्षों तक आठ प्रतिशत की प्रति व्यक्ति वृद्धि और नौ प्रतिशत की वास्तविक वार्षिक वृद्धि की रफ्तार कायम रखनी होगी।

उदय कोटक@udaykotak

भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने पर शुभांगी स्वरूप को बधाई। आप देश की तमाम युवतियों की प्रेरणा हैं। आप हमेशा बुलंदियों पर रहें।

अशोक गहलोत@ashokgehlot51

चे ग्वेरा कम्युनिस्ट शासन वाले केरल के नए भगवान बन गए हैं जहां हिंदू मंदिरों का नियंत्रण सरकार के हाथ में है और हिंदू कार्यकर्ताओं के जीवन पर हरदम खतरा मंडराता रहता है।

डॉ. डेविड फ्राउली@davidfrwleyed

जनपथ

जैसे था लादेन का पहले हुआ इलाज,
हाफिज का भी उस तरह होना चहिए आज।
होना चहिए आज न करिए हल्ला-गुल्ला,
कर दें उसको ठीक जाय बस चार गुरिल्ला!
चुनिए चंद जवान आज फिर बिल्कुल वैसे,
'पंज पियारे' ढूंढ लिए थे 'गुरु' ने जैसे।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।